शिक्षा में लैंगिक भेद- भाव एक समाजशास्त्रीयअध्ययन

डॉ० राम समुझ सिंह, एसोशिएट प्रो० समाजशास्त्र लाल बहादुर शास्त्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोण्डा, उ० प्र०।

सार

बाल अधिकारों पर कन्वेंशन का अनुसमर्थन और भारत द्वारा महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन, साथ ही साथ ग्लोबल फिट फॉर चिल्ड्रन दायित्वों पर हस्ताक्षर, सरकार और नागरिक समाज के लिए एक ढांचा प्रदान करते हैं प्रतिबद्ध कार्रवाई करने के लिए बड़ा।दिसंबर 2002 के संवैधानिक कानून ने 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को एक बुनियादी अधिकार घोषित किया, जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार का सभी के लिए शिक्षा अभियान, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने का एक राष्ट्रीय प्रयास था।भारत की नीतियों और आगे की सोच वाले कानून के साथ-साथ संरचनाओं और संगठनों के भीतर शामिल इसकी मजबूत शैक्षिक प्रथाओं के बीच एक महत्वपूर्ण असमानता है। लिंग मानदंड और अप्रचलित रीति-रिवाज अक्सर लड़कियों और महिलाओं को बांधते हैं, लैंगिक असमानताओं को उजागर करते हैं।लड़कों की तुलना में लगभग दोगूनी लडिकयों को स्कूल से निकाल दिया जाता है या उन्हें कभी स्कूल नहीं भेजा जाता है, खासकर यदि वे एक सामाजिक और आर्थिक समूह से संबंधित हैं जो उन्हें नीचा दिखाता हैं।कई लडिकयां जो दस या ग्यारह साल की उम्र में स्कूल छोड़ देती हैं, अपने भविष्य को खेतों में या सड़क निर्माण परियोजनाओं में काम करने और आजीविका कमाने के रूप में देखती हैं।संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) के अनुसार गरीबी और स्थानीय सांस्कृतिक रीति-रिवाज पूरे भारत में स्कूली शिक्षा में लैंगिक असमानता में एक भूमिका निभाते हैं।महिलाओं की शिक्षा में एक और बाधा देश भर के स्कूलों में स्वच्छता की कमी है।कई स्कूलों में महिलाओं के लिए अलग से शौचालय की सुविधा नहीं है।जब महिलाएं किशोरावस्था में आती हैं, तो उन्हें अलग से शौचालय की सुविधा की आवश्यकता होती है।कई महिलाएं स्कूल छोड़ देती हैं क्योंकि उनके पास मासिक धर्म से निपटने के लिए आवश्यक गोपनीयता और सुविधाओं की कमी होती है।भारत में, 23 प्रतिशत लड़कियां यौवन तक पहुंचने पर स्कूल छोड़ देती हैं।इसके अलावा, जो महिलाएं अपनी शिक्षा जारी रखती हैं, उन्हें मासिक धर्म के कारण हर साल 50 स्कूल के दिन याद आ सकते हैं।

भारतीय समाज में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव

भारत में लैंगिक असमानता बरकरार है।भारतीय संस्कृति में, एक महिला के रूप में पैदा होने का अर्थ है सभी स्तरों पर लैंगिक भेदभाव का सामना करना।महिलाओं को, उनकी शिक्षा या कार्य विवरण की परवाह किए बिना, घरेलू कार्यों, बच्चों की परविरश और घरेलू स्तर पर परिवारों की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया जाता है।महिलाओं के पास किरयर की संभावनाओं तक कम पहुंच है और उनकी कंपनी में समान कार्य के लिए उन्हें कम भुगतान किया जाता है।

महिलाओं के खिलाफ भेदभाव

लिंग भेदभाव को किसी के लिंग के कारण असमान या प्रतिकूल व्यवहार के रूप में परिभाषित किया गया है।पुरुषों की तुलना में महिलाओं को लैंगिक भेदभाव का सामना करने की अधिक संभावना है।शिक्षा और

International Journal of Research in Economics and Social Sciences (IJRESS)

Vol. 6 Issue 10, October 2016,

ISSN(O): 2249-7382, | Impact Factor: 6.225|

सीखने के अवसर: भारत में लिंग साक्षरता के आँकड़े पुरुषों और मिहलाओं के बीच एक महत्वपूर्ण असमानता को प्रकट करते हैं।2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, पुरुषों की प्रभावी साक्षरता दर 82.14 प्रतिशत थी जबिक मिहलाओं की प्रभावी साक्षरता दर 65.46 प्रतिशत थी।माता-पिता लड़िकयों की शिक्षा पर पैसा लगाने से हिचिकचाते हैं क्योंकि उनका मानना है कि मिहलाओं को शिक्षित करना व्यर्थ है क्योंकि वे भविष्य में केवल अपने जीवनसाथी और ससुराल वालों की सेवा करेंगी।भारतीय संविधान पुरुषों और मिहलाओं को समान अधिकारों और लाभों की गारंटी देता है, हालांकि भारत में अधिकांश मिहलाओं के पास इन अधिकारों और अवसरों तक पहुंच नहीं है।यह विभिन्न कारकों के कारण है।

<u> लिंग असमानता कारक:</u>

गरीबी को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

पितृसत्तात्मक भारतीय समाज में लैंगिक भेदभाव का यह मुख्य कारण है, क्योंकि पुरुष समकक्ष पर आर्थिक निर्भरता अपने आप में लिंग असंतुलन का एक स्रोत है।जनसंख्या का तीस प्रतिशत गरीबी में रहता है, जिसमें महिलाओं की संख्या 70 प्रतिशत है

हमारे भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था है।

भारत में, पुरुष समाज और पारिवारिक जीवन पर हावी हैं।

यह सिदयों से मामला रहा है और अभी भी अधिकांश घरों में इसका अभ्यास किया जाता है।

हालांकि शहरीकरण और शिक्षा के परिणामस्वरूप यह रवैया बदल रहा है, फिर भी स्थिति को स्थायी रूप से बदलने के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है।

सामाजिक विश्वास, रीति-रिवाज और व्यवहार -

कई परिवार अब लडकी की जगह लडके को पसंद करते हैं।

बेटों को, विशेष रूप से व्यवसाय में, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक संपत्ति के रूप में देखा जाता है, जबकि लड़कियों को देनदारियों के रूप में माना जाता है।

महिलाओं में जागरूकता की कमी-

अधिकांश महिलाएं अपने मूल अधिकारों और क्षमता से अनिभज्ञ हैं।

उन्हें इस बात का मूलभूत ज्ञान नहीं है कि सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक कारक उन्हें कैसे प्रभावित करते हैं।

वे उन सभी भेदभावपूर्ण व्यवहारों को स्वीकार करते हैं जो पीढ़ी से पीढ़ी तक परंपरा और समाज की परंपराओं के नाम पर उनकी अज्ञानता और अज्ञानता के कारण पारित किए जाते हैं। भारत में लिंग आधारित पूर्वाग्रह को तभी कम किया जा सकता है जब लड़िकयों को पढ़ने और जीवन में आगे बढ़ने के अवसर से वंचित न किया जाए।शैक्षिक संभावनाओं की दृष्टि से लड़िकयों को भी लड़कों की तरह जीवन में आगे बढ़ना चाहिए।इससे उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद मिलेगी और वे अपने और समाज के उत्थान में योगदान देने के लिए उचित रूप से तैयार होंगे।

Vol. 6 Issue 10, October 2016,

ISSN(O): 2249-7382 , | Impact Factor: 6.225 |

प्राथमिक शिक्षा में लैंगिक असमानता: भारत में अनुभव

शिक्षा में असमानता एक संस्कृति में स्पष्ट हो सकती है, जैसे कि जाति, धर्म और लिंग, जैसे कई वितरणों के माध्यम से भारत के रूप में पूरी तरह से स्तरीकृत।हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि ऐसे गरीब समूहों के भीतर भी, शैक्षिक उपलब्धि में पर्याप्त लिंग असमानताओं का एक सतत पैटर्न बना हुआ है। अनुसूचित जाति और जनजाति की लड़िकयों के लिए स्कूली शिक्षा में लिंग अंतर मूल स्तर पर 30% और उच्च प्राथमिक स्तर पर 26% से अधिक है। भारत के सबसे गरीब जिलों में लड़िकयों की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने की संभावना पुरुषों की तुलना में 42% कम है, और यह धर्म और जाति जैसे अन्य कारकों के समायोजित होने के बाद भी बनी रहती है। इस अंतर को पाटने के लिए एक साहसिक और आविष्कारशील नीति की आवश्यकता होगी। इसे स्वीकार करते हुए, भारत सरकार ने महिला शिक्षा को प्राथमिकता दी है। सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), या "सभी के लिए शिक्षा", सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए इसकी प्रमुख पहल, महिला शिक्षा और लिंग समानता पर विशेष जोर देती है। बेशक, क्या यह 2015 में एमडीजी की समय सीमा तक पूरा किया जा सकता है, यह देखा जाना बाकी है। सामाजिक मुद्दों को वित्तीय परिप्रेक्ष्य में लेना।

महिला शिक्षा के लिए सामाजिक बाधाओं को एक बहुत बड़े सामाजिक ताने-बाने के हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसने लैंगिक असमानता के कई संस्थानों का निर्माण किया है। परंपरागत रूप से, लड़के की शिक्षा को एक ऐसे निवेश के रूप में देखा गया है जिससे परिवार की मजदूरी और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी; हालाँकि, अन्य मानदंड महिलाओं पर लागू होते हैं। एक लडकी की शिक्षा के लाभों को अक्सर उस घर में अर्जित होने के रूप में देखा जाता है जिसमें वह शादी करती है, इस तरह की गतिविधि में सीमित संसाधनों, मानव और मौद्रिक दोनों को समर्पित करने के लिए बहुत कम प्रेरणा प्रदान करती है।इसके अलावा, अपेक्षाकृत कम शैक्षिक उपलब्धि को देखते हुए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, एक शिक्षित महिला की विवाह योग्यता की अपनी चुनौतियां हैं।ये ताकतें उन विचारों को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करती हैं जो मूल रूप से महिला शिक्षा के प्रतिकृल हैं।हालाँकि, ये विचार भारत के भीतर भी बहुत भिन्न हैं, इसे दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित करते हुए, दक्षिणी और पश्चिमी राज्य उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों की तुलना में शिक्षा में बहुत उन्नत हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि पंजाब और हरियाणा जैसे समृद्ध राज्यों के साथ-साथ बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे गरीब राज्यों में महिला विरोधी पूर्वाग्रह सबसे अधिक है।हालांकि यह दावा करना गलत होगा कि शैक्षिक पहुंच की गारंटी में वित्तीय चर का कोई प्रभाव नहीं है, यह तर्क देना उचित है कि वे लिंग समानता के एक विश्वसनीय भविष्यवक्ता से बहुत दूर हैं। यदि मुद्दा विशुद्ध रूप से वित्तीय था, तो 2002 का 86वां संशोधन अधिनियम, जिसमें सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का वादा किया गया था. और इसके बाद प्राथमिक शिक्षा के लिए लगातार बढते बजटीय आवंटन के परिणामस्वरूप बुनियादी शिक्षा के स्तर में लगातार वृद्धि होनी चाहिए थी। .

इस तथ्य के बावजूद कि वित्तीय चिंताओं को संभाला गया है, आंकड़े उतनी तेजी से नहीं बढ़े हैं जितना कि अध्ययनों ने भविष्यवाणी की थी। यह उद्देश्य को पूरा करने के लिए सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं के कम आंकने के कारण हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय में वर्ल्ड इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स रिसर्च (WIDER) द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, पारिवारिक वित्तीय क्षमता में वृद्धि से दोनों लिंगों की उपस्थिति पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ा, इसने लड़कियों की शिक्षा दर को लगभग दोगुना प्रभावित किया। लड़कों की। मामूली रूप से बेहतर वित्तीय परिस्थितियों को देखते हुए, शिक्षा प्राप्त करने

International Journal of Research in Economics and Social Sciences (IJRESS)

Vol. 6 Issue 10, October 2016,

ISSN(O): 2249-7382, | Impact Factor: 6.225|

वाली महिलाओं की संख्या में परिवर्तन की गित लड़कों की दर की तुलना में लगभग दोगुनी हो गई है। वित्तीय प्रतिबंध विशेष रूप से महिलाओं की शिक्षा के लिए एक प्रमुख बाधा है।यह तर्क देना असंभव है कि लड़कों की शिक्षा की तुलना में महिलाओं की शिक्षा को सामाजिक और वित्तीय सहायता बहुत कम मिलती है।सरकार की ओर से प्रतिक्रिया। भारत सरकार इस तरह के खुलासे के बाद भी चुप नहीं बैठी है. मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के वादे का पूरे जोश के साथ पालन किया गया है। लैंगिक असमानताओं को कम करने के लिए एसएसए के विशेष कार्यक्रमों पर विचार करने से पहले, संगठन के मूल तत्वों का विश्लेषण करना आवश्यक है।

एसएसए ने दो-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है: पूरे देश में गुणवत्ता और विकास की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्यों और मानकों को केंद्रीय रूप से पिरभाषित करना; और सामुदायिक समूहों और गैर-सरकारी संगठनों की मदद से स्थानीय प्रबंधन और बॉटम-अप योजना योजनाओं का एक व्यापक नेटवर्क स्थापित करना। प्रत्येक राज्य एक नई पिरयोजना शुरू करने से पहले क्षेत्र में बच्चों की संख्या, उम्र और लिंग का पता लगाने के लिए एक जनगणना करने के लिए बाध्य है। डेटा का उपयोग वार्षिक कार्य योजना बनाने के लिए किया जाता है, जिसे बाद में केंद्र सरकार के साथ प्रस्तुत किया जाता है तािक प्रदान किए गए और खर्च किए गए धन की जिम्मेदारी सुनिश्चित हो सके। राज्यों को प्राथमिक शिक्षा पर वास्तविक मूल्य व्यय के 1999 के स्तर को बनाए रखने और इन क्षेत्रों में बढ़े हुए संघीय समर्थन की बराबरी करने के लिए मजबूर किया गया है, जो एक सकारात्मक कदम है।

यह गारंटी देता है कि शिक्षा के लिए वित्तीय प्रतिबद्धता बनाए रखी जाती है, और बजटीय आवंटन में वृद्धि अंतिम प्राप्तकर्ताओं तक पहुंचती है।एसएसए महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान देता है। इस संबंध में सरकारी उपायों को दो व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: एक का उद्देश्य लड़िकयों की स्कूल पहुंच और प्रतिधारण में सुधार के लिए "पुल कारक" बनाना है, और दूसरा उद्देश्य समाज में लड़िकयों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक परिस्थितियों को पोषित करने के लिए "पुश कारक" बनाना है। शिक्षा।आज, स्कूल में आठवीं कक्षा तक की सभी लड़िकयों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें मिलती हैं, और बड़ी उम्र की महिलाओं के लिए बैक-टू-स्कूल कैंप और ब्रिज कोर्स आयोजित किए जाते हैं।

निष्कर्ष

भारत में अधिकांश सार्वजिनक बहसें पितृसत्तात्मक मानकों को पुष्ट करती हैं जैसे कि कानून में संशोधन और अद्यतन करना और लैंगिक समानता के लिए मिहला आंदोलनों का समर्थन करना।शिक्षा, सामान्य रूप से, और विशेष रूप से मिहलाओं की शिक्षा, भारत में दीर्घकालिक सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण है।इसका कारण यह है कि यह पूरी दुनिया में मिहलाओं के साथ उनके विचारों और धारणाओं को संशोधित करता है, जिसके पिरणामस्वरूप व्यवहार के नए रूप, दूसरों से जुड़ने के तरीके और अंततः, सामाजिक मानकों का पिरणाम होता है।उदाहरण के लिए, यिद उपरोक्त अभ्यास का पालन किया जाता है, तो वे शिक्षा के महत्व की सराहना करेंगे और अपनी मिहला संतानों को शिक्षित करेंगे, जो भारत में लिंग मानदंडों को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।इसके अलावा, मीडिया, सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से उत्पीड़ित परिवारों के लिए कार्यक्रमों और छात्रवृत्ति के उचित ज्ञान को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।यह उनके माता-पिता को अपने व्यक्तिगत घरों को खतरे में डाले बिना उन्हें स्कूल और

आगे की शिक्षा प्राप्त करने की अनुमित देने के लिए राजी कर सकता है।इसके अलावा, रोजगार नीति में बदलाव किया जाना चाहिए ताकि मिहलाओं को पुरुषों के समान भुगतान किया जा सके, जो आर्थिक विकास और एक प्रगतिशील देश के निर्माण के लिए मिहलाओं के आर्थिक जुड़ाव को प्रोत्साहित कर सके।

संदर्भ

- 1. दिज्क्स्ट्रा; हनमर (२०००)। "सामाजिक-आर्थिक लैंगिक असमानता को मापना: यूएनडीपी लिंग-संबंधी विकास सूचकांक के विकल्प की ओर"। नारीवादी अर्थशास्त्र। 6 (२): 41-75. डोई:10.1080/13545700050076106. एस2सीआईडी 15457819
- 2. कुंडू, सुभाष सी. (2003)। "कार्यबल विविधता की स्थिति: कर्मचारियों की प्रतिक्रियाओं का एक अध्ययन"। औद्योगिक प्रबंधन और डेटा सिस्टम। 103 (4): 215-226।
- 3. पांडे, एस्टोन (2007). "ग्रामीण भारत में बेटे की वरीयता की व्याख्या: संरचनात्मक बनाम व्यक्तिगत कारकों की स्वतंत्र भूमिका"। जनसंख्या अनुसंधान और नीति समीक्षा। 26: 1-29।
- 4. मासेल्को, जे; परेल, विक्रम (२००८)। "महिलाएं आत्महत्या का प्रयास क्यों करती हैं: भारत में एक सामुदायिक समूह अध्ययन में मानसिक बीमारी और सामाजिक नुकसान की भूमिका"। जर्नल ऑफ़ एपिडेमियालॉजी और कम्युनिटी हेल्थ। 62 (9): 817-822। डीओआई: 10.1136/जेच.2007.069351। पीएमआईडी 18701733। एस2सीआईडी 12589827।
- 5. पटेल, विक्रम; किर्कवुड, बेट्टी आर.; पेडनेकर, सुलोचना; परेरा, बर्नडेट; बैरोस, प्रीतम; फर्नांडीस, जेनिस; दत्ता, जेन; पाई, रेशमा; वीस, हेलेन (1 अप्रैल 2006)। "महिलाओं में सामान्य मानसिक विकारों के लिए लिंग हानि और प्रजनन स्वास्थ्य जोखिम कारक"। सामान्य मनश्चिकित्सा के अभिलेखागार। 63 (4): 404-13। doi:10.1001/archpsyc.63.4.404। आईएसएसएन 0003-990X। पीएमआईडी 16585469।
- 6. श्मलेगर, जॉन हम्फ्री, फ्रैंक (29 मार्च 2011)। विचलित व्यवहार (दूसरा संस्करण)। सडबरी, एमए: जोन्स एंड बार्टलेट लर्निंग। पी। 252. आईएसबीएन 978-0763797737।
- 7. लॉर्बर, जे। (1994)। लिंग के विरोधाभास। येल यूनिवर्सिटी प्रेस, पेज 2-6, 126-143, 285-290
- 8. कबीर, नैला (1996). "एजेंसी, भलाई और असमानता: गरीबी के लिंग आयामों पर विचार"। आईडीएस बुलेटिन (प्रस्तुत पांडुलिपि)। 27 (1): 11-21. doi:10.111/j.1759-5436.1996.mp27001002.x1